भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2624
दिनांक 05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

डेयरी सहकार योजना

2624. श्री अरुण भारतीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डेयरी सहकार योजना के अंतर्गत 2025 में उपयोग की गई 5,000 करोड़ रुपये की निधि का व्यय संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों की तुलना में 2025 में स्थापित डेयरी सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
(ग) क्या इस योजना के चारा विकास कार्यक्रमों से 2025 में सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में दूध उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के डेयरी उत्पादों की ब्रांडिंग और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस योजना ने 2025 में मोबाइल पशु चिकित्सा देखरेख और कृत्रिम गर्भाधान में नवाचारों की सहायता की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डेयरी उत्पादकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) डेयरी सहकार, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सांविधिक निगम- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) का एक व्यापक फ्रेमवर्क है। एनसीडीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डेयरी सहकार फ्रेमवर्क का उद्देश्य देश भर में डेयरी सहकारी समितियों को अवसंरचना के निर्माण के साथ-साथ डेयरी सहकारी समितियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करना है। इसमें सहकारी समितियों का गठन शामिल नहीं है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत, एनसीडीसी द्वारा कोई विशिष्ट निधि आबंटित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ समन्वय करके और स्वयं भी देश भर में पात्र डेयरी सहकारी समितियों को राज्य सरकार/ प्रत्यक्ष वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, एनसीडीसी ने 13.325 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अंतर्गत एनसीडीसी द्वारा संवितरित निधियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य**	**लाभार्थी**	**संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)**
1.	गुजरात	गांधीनगर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लि.	0.71
2.	तमिलनाडु	थूटुकुडी जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लि.	12.49
3.	ओडिशा	कटक जिला सहकारी दूध संघ प्रा. लि.	0.125
कुल			**13.325**

(ग) से (ङ) एनसीडीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चारा विकास, ब्रांड और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने, मोबाइल पशु चिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान के लिए वर्ष 2025 में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****